राजपाट प्रभात

शासन विभाग का सालाना बजट आकार 1032.82 करोड़ रुपये का है.

कार्यशाला. बिहार रेरा के अध्यक्ष ने प्रोमोटर्स को दी चेतावनी

सेटेलाइट इमेज से अब रियल इस्टेट परियोजनाओं की होगी मॉनीटरिंग

संवाददाता, पटना

- एक अक्तूबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 के बीच पूरी होने वाली 98 रजिस्टर्ड परियोजनाओं में 33 पर अब तक सही ढंग से काम भी शुरू नहीं हुआ

रजिस्टर्ड परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) नयी तकनीकों की मदद लेगी. प्राधिकरण जल्द ही सेटेलाइट इमेज और ड्रोन फोटोग्राफी की सहायता लेकर रेरा कानून नहीं मानने और इसका उल्लंघन करने वाले प्रोमोटरों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी. शुक्रवार को प्रोमोटरों की एक जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिहार रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने यह चेतावनी दी. इस कार्यशाला में वैसे प्रोमोटर्स को बुलाया गया था जिनकी परियोजना का रजिस्ट्रेशन एक अक्तूबर, 2024 और 31 मार्च, 2025 के बीच समाप्त होने वाला है. प्रोमोटरों की तिमाही रिपोर्ट के आधार पर कार्यशाला में बताया कि 98 रजिस्टर्ड परियोजनाओं का निबंधन 31 मार्च ,2025 तक समाप्त होने वाला है. इनमें से 55 परियोजनाएं पूरी होने के कगार पर हैं. इनके अलावा 11 परियोजनाओं की प्रगति धीमी है, जबकि 32 परियोजनाओं अब तक ढंग से शुरू भी नहीं हो पायी हैं. रेरा अध्यक्ष ने कहा कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा सर्वोपरि है. इसके लिए जरूरी है कि निबंधित परियोजनाएं समय पर पूरी हों. कार्यशाला का उद्देश्य निबंधन समाप्त होने से पहले समय पर हस्तक्षेप करना है. उन्होंने कहा कि हम प्रोमोटरों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर परियोजना की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, तो उन्हें रजिस्टर्ड परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पहले से ही सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए.

कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिहार रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह.

शक पैदा करती है परियोजनाओं की धीमी प्रगति

रेरा बिहार के सदस्य एसडी झा ने कहा कि परियोजनाओं की धीमी प्रगति यह दिखाती है कि ऐसे प्रोमोटरों को अपने ग्राहकों के हितों की चिंता नहीं है. धीमी गति से चल रही परियोजनाओं से यह भी शक पैदा होता है कि ग्राहकों के पैसों का सही उपयोग नहीं हो रहा है. कार्यशाला में न्यायनिर्णायक अधिकारी एके तिवारी, सचिव आलोक कुमार, ओएसडी राजेश बदानी, वरिष्ठ कानूनी सलाहकार वेद प्रकाश और वरिष्ठ भू अभिलेख अधिकारी अमरेंद्र शाही सहित रेरा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया.

मालूम हो कि रेरा ने इससे पहले 28 मई को उन परियोजनाओं के प्रोमोटरों के लिए कार्यशाला आयोजित की थी, जिनका निबंधन 30 सितंबर ,20224 तक समाप्त होने वाला है.